कार्यकारी सारांश

इस प्रतिवेदन में एक निष्पादन लेखापरीक्षा (पीए), एक विषय-विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा (एसएससीए) और तीन पृथक अनुपालन लेखापरीक्षा कंडिकाएं शामिल हैं।

महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा टिप्पणियों पर निम्नलिखित कंडिकाओं में संक्षेप में चर्चा की गई है:

झारखंड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड के कार्यप्रणाली पर निष्पादन लेखापरीक्षा

झारखंड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड (झा.रा.भ.नि.नि.लि.) एक राज्य सरकार के स्वामित्व वाली कंपनी है जिसकी स्थापना नवंबर 2015 में झारखंड में सार्वजनिक बुनियादी ढाँचे और सरकारी परियोजनाओं के निर्माण, विकास और रखरखाव के प्रबंधन के लिए की गई थी। कंपनी का उद्देश्य विभिन्न सरकारी विभागों को कुशल परियोजना प्रबंधन सेवाएँ प्रदान करके राज्य के बुनियादी ढाँचे के विकास में सहयोग करना है।

झा.रा.भ.नि.नि.लि. के कार्यप्रणाली पर लेखापरीक्षा का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि क्या: कॉर्पोरेट बजट तैयार किया गया था, और वित्तीय प्रबंधन प्रभावी था; परियोजनाओं के लिए नियोजन प्रक्रिया प्रभावी थी; परियोजनाओं का क्रियान्वयन किफायती, कुशल और प्रभावी था; एक प्रभावी निगरानी और मूल्यांकन तंत्र मौजूद था; और एक प्रभावी आंतरिक नियंत्रण और शिकायत निवारण प्रणाली मौजूद थी।

मुख्य लेखापरीक्षा निष्कर्ष इस प्रकार हैं:

कंपनी ने ₹14,020.46 करोड़ की कुल लागत वाली 1,328 कार्य परियोजनाएँ (नवंबर 2015 में स्थापना से मार्च 2023 तक) शुरू की थीं। इनमें से ₹4,291.07 करोड़ मूल्य के 726 कार्य (55 प्रतिशत) पूरे हो चुके थे; 218 कार्य प्रगति पर थे (₹1,630.80 करोड़); 272 कार्य प्रारंभिक चरण में थे; और 112 कार्य भूमि की अनुपलब्धता, सार्वजनिक बाधाओं, संवेदकों द्वारा विलंब आदि के कारण या

तो रद्द कर दिए गए या रोक दिये गए (₹194.92 करोड़) कंपनी ने 24 कार्यों के निष्पादन के लिए उपयोगकर्ता विभागों से प्राप्त ₹ 60.95014 करोड़ वापस नहीं किए थे, जिन्हें बाद में छोड़ दिया गया था, और इस राशि को चार से सात वर्षों की अवधि के लिए अपने व्यक्तिगत लेजर खाते में रखा था।

कंपनी ने 2018-19 से 2022-23 के दौरान न तो कॉर्पोरेट बजट तैयार किया और न ही विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) की समीक्षा और कार्यों की प्रगति की निगरानी के लिए कोई तकनीकी समिति गठित की। वास्तविक स्थल स्थितियों पर आधारित विस्तृत अनुमान के बिना इसने सलाहकारों द्वारा तैयार किए गए मॉडल अनुमानों के आधार पर परियोजनाओं का क्रियान्वयन शुरू कर दिया। इसके अलावा, विभिन्न कार्यों के लिए आवश्यक भूमि या तो उपयोगकर्ता विभागों द्वारा सौंपी ही नहीं गई या विलंब से सौंपी गई। परिणामस्वरूप, ₹102.87 करोड़ मूल्य के 35 कार्य अधूरे रह गए थे।

लेखापरीक्षा ने यह भी पाया कि हाई टेंशन संचरण लाइन के आसपास भवनों के निर्माण के प्रतिकूल प्रभाव का पूर्वानुमान लगाने में कंपनी की असमर्थता के कारण एक डिग्री कॉलेज का पूरा हो चुका भवन बेकार पड़ा रहा, जिससे ₹12 करोड़ का व्यय निष्फल रहा। इसके अलावा, डांडा और बिष्णुपुरा में झारखंड बालिका आवासीय विद्यालयों (जेबीएवी) के आंशिक रूप से पूर्ण ढाँचों पर ₹5.60 करोड़ का व्यय निष्फल रहा, जबकि संगमा में जेबीएवी के परित्यक्त ढाँचे पर ₹2.80 करोड़ का व्यय संवेदकों द्वारा काम रोक दिए जाने के बाद व्यर्थ हो गया।

(कंडिका 2.5.1 एवं 2.5.2)

परियोजना कार्यान्वयन इकाइयों में, विशेष रूप से सहायक अभियंताओं (88 प्रतिशत) और कनिष्ठ अभियंताओं (75 प्रतिशत) के पदों पर, कर्मचारियों की भारी कमी थी। कर्मचारियों की कमी परियोजनाओं के अपर्याप्त आंतरिक नियंत्रण और निगरानी का एक कारण थी, जिसके कारण परियोजनाओं के पूरा होने में विलंब हुई या वे पूरी नहीं हो पाईं।

(कंडिका 2.5.3)

लेखापरीक्षा ने 206 कार्यों की जांच की और अनुबंध प्रबंधन में कमियां पाईं - बोलियां प्रस्तुत करने के लिए अपर्याप्त समय का प्रावधान; पारदर्शिता की कमी; अपर्याप्त बोली मूल्यांकन; अनुबंध के निष्पादन में विलंब; अनियमित भुगतान; अनुपूरक अनुबंध में अनियमितताएं; और बीमा द्वारा कवर नहीं किए गए कार्य।

बोली क्षमता निर्धारित करने के लिए, कंपनी ने निष्पादित सिविल इंजीनियरिंग कार्यों के अधिकतम मूल्य के बजाय वार्षिक खातों से प्राप्त अनुबंध कार्यों / संचालन से राजस्व से सकल प्राप्ति के मूल्य पर विचार किया, जिसके परिणामस्वरूप 20 अयोग्य बोलीदाताओं का चयन किया गया।

(कंडिका 2.5.4.1)

कार्यों के निष्पादन में खामियों के कारण संवेदकों को अधिक भुगतान के कई मामले सामने आए। सात परियोजनाओं में, मूल्य समायोजन के गलत निर्धारण के कारण ₹1.76 करोड़ का अधिक भुगतान हुआ। डिग्री कॉलेजों के भवनों के निर्माण के लिए, आवश्यक तीन-स्टॉप लिफ्टों के बजाय दो छह-स्टॉप यात्री लिफ्टों का प्रावधान किया गया, जिसके परिणामस्वरूप ₹2.60 करोड़ का अतिरिक्त प्रावधान हुआ, जिसमें नमूना-जाँचित 11 कार्यों में ₹2.15 करोड़ का अतिरिक्त भुगतान किया गया।

(कंडिका 2.5.5.1 एवं 2.5.5.2)

झारखंड रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय के स्थायी परिसर का निर्माण कार्य जून 2018 में शुरू किया गया था, जिसे मई 2020 तक पूरा करना था। विभाग के निर्देशों (मई 2021) के आधार पर, ₹12.10 करोड़ खर्च करने के बाद जुलाई 2021 में कार्य बंद कर दिया गया। तब से भवन का अधूरा ढांचा बेकार पड़ा था। इसी तरह, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, पर्यटन विकास कार्य, परिसर की दीवार का निर्माण और 5000 मीट्रिक टन कोल्ड स्टोरेज से संबंधित छहः कार्य दिसंबर 2011 और मई 2020 के बीच पूरे होने थे। हालांकि, आंशिक रूप से पूरा होने (अक्टूबर 2023 तक भौतिक प्रगति 20 से 76 प्रतिशत के बीच थी) और ₹13.32 करोड़ खर्च करने के बाद कार्य बीच में ही रोक दिया गया/ठप कर दिया गया।

(कंडिका 2.5.5.3 एवं 2.5.5.4)

नौ उपयोगकर्ता विभागों से संबंधित 33 कार्य क्रियान्वयन के दौरान उचित निगरानी के अभाव में ₹ 1,693.31 करोड़ के भुगतान के बाद तीन महीने से लेकर चार वर्षों के बीच की विलंब से पूरे हुए और चार उपयोगकर्ता विभागों से संबंधित 14 कार्य ₹ 669.98 करोड़ के व्यय के बाद एक वर्ष से लेकर सात वर्षों से अधिक की विलंब से अधूरे रह गए।

छहः कार्यों (स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग के पाँच कार्य और कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग का एक कार्य) में से केवल दो कार्य (प्रत्येक विभाग का एक-एक) तीन से चार वर्षों की विलंब से पूरे हुए, जबकि चार कार्य दो से आठ वर्षों की विलंब से अधूरे रह गए (जुलाई 2024 तक)। लेखापरीक्षा ने पाया कि कार्य स्थलों को सौंपने में विलंब हुई, चित्र और डिज़ाइन आदि उपलब्ध होने में विलंब हुई। इसके परिणामस्वरूप इन छहः कार्यों की लागत में ₹42.32 करोड़ की वृद्धि हुई, जो विस्तारित अवधि के दौरान मूल्य समायोजन था।

(कंडिका 2.5.5.9)

नमूना-जाँचित 46 पूर्ण कार्यों में से, 37 कार्य दो वर्ष से अधिक की विलंब से उपयोगकर्ता विभागों को सौंपे गए और शेष नौ कार्य, उनके पूरा होने के लगभग चार वर्ष बाद भी नहीं सौंपे गए। सौंपने में विलंब का मुख्य कारण उपयोगकर्ता विभागों और कंपनी के बीच समन्वय का अभाव था। परिसंपत्तियों को सौंपने में अत्यधिक विलंब से न केवल भवनों की स्थिति खराब होने का खतरा बढ़ जाता है, बल्कि इच्छित लाभार्थियों को इन भवनों के उपयोग के अवसर से भी वंचित होना पड़ता है। इसके अलावा, भवन से चोरी हुए कई उपकरणों की मरम्मत और पुनर्खरीद पर ₹2.43 करोड़ का अनावश्यक व्यय हुआ।

(कंडिका 2.5.5.10)

कंपनी ने तकनीकी व्यवहार्यता और आर्थिक व्यवहार्यता सुनिश्चित करने के लिए डीपीआर का मूल्यांकन करने हेतु, आवश्यकतानुसार, एक तकनीकी समिति का गठन नहीं किया था। निर्माण सामग्री के पूर्व-परीक्षण के लिए परीक्षण प्रयोगशालाओं को भी सूचीबद्ध नहीं किया गया था और न ही रेखाचित्रों और

डिज़ाइनों में बदलावों को मंज़ूरी देने के लिए कोई आंतरिक डिज़ाइन विंग स्थापित किया गया था।.

(कंडिका 2.5.6)

अनुशंसाएं:

- ***कंपनी अपने पीएल खाते में पड़े अप्रयुक्त धन को उपयोगकर्ता विभागों को समय पर वापस करना सुनिश्चित करे।***
- ***कंपनी कार्य प्रारंभ होने से पहले तकनीकी व्यवहार्यता का आकलन करने हेतु तकनीकी समिति का गठन सुनिश्चित करने हेतु शीघ्र कार्रवाई करे। इसके अतिरिक्त, जेएसबीसीसीएल वास्तविक स्थल स्थितियों के आधार पर विस्तृत अनुमान, रेखाचित्र और डिज़ाइन तैयार करने के बाद ही कार्य प्रारंभ करना सुनिश्चित करे।***
- ***कंपनी सबसे अधिक प्रतिस्पर्धी मूल्य प्राप्त करने के लिए एक पारदर्शी और एकसमान बोली प्रणाली स्थापित और कार्यान्वित कर सकती है। वह संवेदकों के साथ हस्ताक्षरित समझौतों की शर्तों और नियमों का पालन भी सुनिश्चित कर सकती है।***
- ***कंपनी परियोजनाओं के अनुमान तैयार करने में उचित सावधानी सुनिश्चित कर सकती है।***
- ***कंपनी समय और लागत में वृद्धि से बचने के लिए समझौते के प्रावधानों के अनुसार कार्यों को समय पर पूरा करने में बाधा डालने वाले मुद्दों को हल करने के लिए प्रभावी निगरानी सुनिश्चित कर सकती है।***
- ***राज्य सरकार कंपनी और उपयोगकर्ता विभागों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित कर सकती है ताकि पूर्ण परिसंपत्तियों को बिना किसी और विलंब के सौंप दिया जा सके और उनका उपयोग इच्छित उद्देश्यों के लिए किया जा सके।***
- ***कंपनी कार्य की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए डिजाइन विंग की स्थापना के साथ-साथ प्रयोगशालाओं का पैनल भी सुनिश्चित कर सकती है।***

झारखंड राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड की खरीद गतिविधि पर विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा

"जेएसएफसीएल की खरीद गतिविधि" पर लेखापरीक्षा यह आकलन करने के लिए की गई थी कि क्या धान की खरीद और किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) का भुगतान समय पर किया गया था; खाद्यान्नों की खरीद और परिवहन कुशलतापूर्वक और मितव्ययिता से किया गया था; गोदामों का प्रबंधन मानक प्रथाओं के अनुसार किया गया था; निधियों का प्रभावी ढंग से उपयोग किया गया था और आंतरिक नियंत्रण/निगरानी तंत्र मौजूद थे।

लेखापरीक्षा के मुख्य निष्कर्ष इस प्रकार हैं:

खरीफ विपणन सीजन (केएमएस) 2018-19 से 2021-22 (जनवरी 2023 तक की अवधि) के दौरान, कंपनी 18.29 लाख मीट्रिक टन के लक्ष्य के मुकाबले केवल 16.47 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद कर सकी, जिसका मुख्य कारण मिल मालिकों द्वारा धान का उठाव न करना और प्राथमिक कृषि ऋण सहकारी समितियों (पीएसीसीएस)/बड़े क्षेत्र बहुउद्देशीय सहकारी समितियों (एलएएमपीएस) के पास सीमित भंडारण क्षमता उपलब्ध होना था।

(कंडिका 3.1.2)

नमूना-जाँचित जिलों में 1,59,354 किसानों से धान की खरीद की गई और एमएसपी का भुगतान दो किस्तों में किया जाना था - 50 प्रतिशत खरीद के अगले दिन और शेष 50 प्रतिशत खरीद की तिथि से एक महीने के अंदर। जाँच से पता चला कि पहली किस्त का भुगतान 79 से 98 प्रतिशत किसानों को भुगतान की निर्धारित तिथि से 775 दिनों तक की विलंब से किया गया था। इसी प्रकार, दूसरी किस्त का भुगतान 64 से 100 प्रतिशत किसानों को 370 दिनों तक की विलंब से किया गया था। इसके अलावा, खरीद की तारीख से आठ महीने से चार साल तक की अवधि बीत जाने के बाद भी, 1,741 किसानों को ₹8.64 करोड़ का एमएसपी भुगतान (अप्रैल 2023) नहीं किया गया।

(कंडिका 3.1.2.1)

नमूना-जाँच किए गए नौ जिलों में केएमएस 2011-12 से 2017-18 के लिए 256 पैक्स/लैम्प्स पर कुल ₹25.10 करोड़ बकाया थे। हालाँकि, ₹9.70 करोड़

बकाया राशि वाली 105 पैक्स/लैम्प्स और ₹7.51 करोड़ बकाया राशि वाली 14 मिलरों को केएमएस 2018-19 से 2021-22 के दौरान मिलिंग के लिए धान खरीदने की अनुमति दी गई थी। इसके अलावा, इनमें से 25 पैक्स/लैम्प्स और चार मिलरों ने केएमएस 2018-19 से 2021-22 के दौरान क्रमशः ₹11.22 करोड़ मूल्य का धान और ₹30.09 करोड़ मूल्य का सीएमआर वितरित नहीं किया था। इन पैक्स/लैम्प्स और मिलरों के खिलाफ कोई कार्रवाई भी नहीं की गई है।

(कंडिका 3.1.3.1)

नमूना-जांचित नौ जिलों में केएमएस 2018-19 से 2021-22 के दौरान किसानों से पैक्स/लैम्पस द्वारा खरीदे गए 10.07 लाख मीट्रिक टन धान में से ₹20.77 करोड़ मूल्य का 10,210 मीट्रिक टन धान मिलरों को नहीं दिया गया। नमूना-जांचित नौ जिलों में से आठ में लेखापरीक्षा जांच से पता चला कि 33 मिलरों ने केएमएस 2018-19 से 2021-22 के दौरान मिलिंग के लिए उनके द्वारा उठाए गए धान के बदले एफसीआई को बराबर मात्रा का सीएमआर जमा नहीं किया था। लेखापरीक्षा द्वारा गणना के अनुसार, 51 चूक अवसरों पर 24,215.17 मीट्रिक टन सीएमआर कम जमा करने के लिए इन 33 मिलरों से ₹72.81 करोड़ की राशि वसूलने योग्य थी।

(कंडिका 3.1.3.2 एवं 3.1.3.4)

नमूना-जांचित जिलों में 83 गोदामों के संयुक्त भौतिक सत्यापन के दौरान, बिजली की कमी (92 प्रतिशत) और तौल कांटों की अनुपस्थिति (100 प्रतिशत), अग्निशमन उपकरण (100 प्रतिशत), सीसीटीवी और सुरक्षा कर्मियों की अनुपस्थिति (100 प्रतिशत) जैसे मुद्दे पाए गए।

(कंडिका 3.1.5.1)

एफसीआई से दावा योग्य ₹692.73 करोड़ के आकस्मिक शुल्कों के विरुद्ध, कंपनी ने केएमएस 2011-12 से 2021-22 के दौरान केवल ₹93.51 करोड़ के दावे प्रस्तुत किए, जिनमें से एफसीआई ने केवल ₹22.88 करोड़ की प्रतिपूर्ति की। कंपनी द्वारा आकस्मिक शुल्कों के कम दावे और एफसीआई द्वारा कम

प्रतिपूर्ति का कारण, कंपनी के वित्तीय विवरणों को अंतिम रूप न देना और एफसीआई को पूर्ण दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत न करना था।

(कंडिका 3.1.3.6)

कंपनी अप्रैल 2016 से मार्च 2022 के दौरान भारतीय खाद्य निगम (FCI) से 88,716 मीट्रिक टन चावल और 29,429 मीट्रिक टन गेहूं नहीं उठा सकी। हालाँकि कंपनी ने इन खाद्यान्नों की लागत के लिए ₹32.50 करोड़ का अग्रिम भुगतान किया था, लेकिन उसने केवल ₹2.42 करोड़ की वापसी का दावा किया।

(कंडिका 3.1.4.1)

कंपनी ने 2019-20 और 2022-23 के बीच निदेशक मंडल की केवल छहः बैठकें आयोजित किये, जबकि इस अवधि के लिए 16 बैठकें करना था।

कंपनी के वार्षिक खाते अपनी स्थापना (जून 2010) से ही बकाया हैं। कंपनी के जिला कार्यालयों द्वारा बुनियादी लेखा अभिलेख, जैसे रोकड़ बही आदि का रखरखाव नहीं किया जाता था और कंपनी ने इसके लिए कर्मचारियों की कमी को जिम्मेदार ठहराया था।

(कंडिका 3.1.6.1)

कंपनी ने 2018-19 के लिए अनंतिम खाते तैयार करने, आयकर रिटर्न दाखिल करने और ऋण प्राप्त करने के लिए दो अलग-अलग चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्मों को नियुक्त किया। लेखापरीक्षा ने पाया कि कंपनी ने एक ही वर्ष के लिए दो अलग-अलग वित्तीय विवरण प्रस्तुत किए - एक में आयकर विभाग को ₹152 करोड़ का घाटा दिखाया गया और दूसरे में बैंक ऑफ इंडिया को ₹96 करोड़ का लाभ दिखाया गया - जो कंपनी के वित्तीय प्रदर्शन का गलत विवरण दर्शाता है।

(कंडिका 3.1.6.3)

बैंक ऑफ इंडिया (BoI) और भारतीय स्टेट बैंक (SBI) को L1 बोलीदाताओं के रूप में चुना गया था, जो ₹776 करोड़ के कार्यशील पूंजी मांग ऋण के लिए 4.5 प्रतिशत प्रति वर्ष की निश्चित ब्याज दर की पेशकश कर रहे थे। चूंकि बाद में सीएजी-लेखापरीक्षित खातों की अनुपस्थिति के कारण SBI ने अपना प्रस्ताव वापस ले लिया, नवंबर 2021 में और फिर दिसंबर 2022 में BoI के साथ

समझौते किए गए थे। ब्याज दर, जो शुरू में तय थी, बाद में बिना किसी दस्तावेजी औचित्य के फ्लोटिंग में बदल दी गई। जुलाई 2023 तक, BoI ने 4.50 और 5.40 प्रतिशत के बीच फ्लोटिंग दर पर ₹1,076 करोड़ का ऋण वितरित किया था। लेखापरीक्षा गणना के अनुसार, निश्चित दर पर देय ब्याज की राशि ₹32.98 करोड़ (21 जुलाई 2023 तक) होती। हालाँकि, कंपनी ने फ्लोटिंग दर पर ₹ 40.68 करोड़ का भुगतान किया, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 7.70 करोड़ का अतिरिक्त ब्याज भुगतान हुआ।

(कंडिका 3.1.6.5)

कुल स्वीकृत 830 पदों (431 नियमित और 399 संविदा) में से केवल 66 कर्मचारी (31 नियमित और 35 संविदा) ही तैनात थे, जिससे 764 पद रिक्त रह गए। इसके अतिरिक्त, कंपनी के निदेशक मंडल की अनुमति के बिना 333 कर्मियों को आउटसोर्सिंग एजेंसी के माध्यम से नियुक्त किया गया।

(कंडिका 3.1.7)

अनुशंसाएं:

- ***कंपनी ई-उपार्जन पोर्टल पर पैक्स/लैम्प्स द्वारा मिल मालिकों को भेजे गए धान की खरीद और मात्रा का विवरण समय पर दर्ज करना सुनिश्चित करे तथा मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) का पालन करे ताकि किसानों को समय पर एमएसपी का भुगतान किया जा सके।***
- ***कंपनी यह सुनिश्चित करे कि पैक्स/लैम्प्स, खरीदे गए धान की पूरी मात्रा मिल मालिकों को और मिल मालिक, सीएमआर की पूरी मात्रा एफसीआई को जमा करें। एमएसपी/बोनस/ब्याज की वसूली के लिए कार्रवाई न करने वाले चूककर्ता पैक्स/लैम्प्स और मिल मालिकों के साथ-साथ विभाग के दोषी अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई की जा सकती है।***
- ***कंपनी सभी आवश्यकताओं के साथ-साथ एमएसपी और पूर्ण आकस्मिक शुल्क के दावों को समय पर एफसीआई को प्रस्तुत करना सुनिश्चित करेगी।***
- ***कंपनी यह सुनिश्चित करने के लिए तत्काल कदम उठाए कि उसके स्थापना से ही खातों को अंतिम रूप दिया जाए और उनका लेखा-परीक्षण***

किया जाए ताकि कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों का अनुपालन किया जा सके और धान खरीद के लिए आकस्मिक प्रभारों के विरुद्ध दावे उठाए जा सकें।

अनुपालन लेखापरीक्षा कंडिकाएं

हालाँकि बोलीदाताओं ने 12 महीनों के भीतर समान दरों पर अतिरिक्त मात्रा में आपूर्ति करने पर सहमति व्यक्त की थी, झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड (JBVNL) ने मौजूदा आपूर्तिकर्ताओं को दोबारा ऑर्डर देने के बजाय उन्हीं वस्तुओं के लिए नए सिरे से निविदाएँ जारी कीं। परिणामस्वरूप, JBVNL ने ऊँची दरें स्वीकार कर लीं, जिससे ₹5.93 करोड़ का अनावश्यक व्यय हुआ। इसके अलावा, उन्हीं चार पूर्व आपूर्तिकर्ताओं को नए क्रय आदेश जारी किए गए, जिससे उन्हें ₹1.79 करोड़ का अनुचित लाभ हुआ।

(कंडिका 3.2.1)

झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड (जेबीवीएनएल) द्वारा वितरण ट्रांसफार्मर (डीटीआर) मीटर और मॉडेम में संचार उपकरण (सिम) की स्थापना न करने से न केवल चार शहरों में डीटीआर मीटर की स्थापना का उद्देश्य विफल हो गया, बल्कि जुलाई 2020 से 4.31 करोड़ रुपये का निष्क्रिय व्यय भी हुआ।

(कंडिका 3.2.2)

झारखंड ऊर्जा उत्पादन निगम लिमिटेड (JUUNL) के प्रबंध निदेशक ने एकल निविदा के आधार पर मरम्मत कार्य सौंपने के लिए विद्युत प्रत्यायोजन (DoP) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग नहीं किया, जिसके परिणामस्वरूप पावरहाउस उपकरणों की मरम्मत के लिए कार्य आदेश को अंतिम रूप देने में विलंब हुई। इसके परिणामस्वरूप, रांची के सिकिदिरी स्थित सुवर्णरेखा जलविद्युत परियोजना में ₹8.46 करोड़ मूल्य की 85 MU विद्युत उत्पादन की हानि हुई, जिसे टाला जा सकता था।

(कंडिका 3.2.3)